RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 19 MAY TO 25 MAY 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 39 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

कंपनियों का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अप्रैल में दोगुना बढ़कर 2.51 अरब डालर पर पहुंचा Page 2

6 महीने में पहली बार होगी जीएसटी की बैठक, इन मुद्दे पर होगा जोर Page 3

कोविड-19 महामारी के समय में प्लास्टिकः रक्षक या प्रदूषक? Page 4

editoria!

आपूर्ति श्रृंखला बाधित

महामारी के असर से उबरने की कोशिश में जुटी वैश्विक अर्थव्यवस्था इन-दिनों एक नयी चुनौती का सामना कर रही है. दुनियाभर में कंपनियां अपनी जरूरत से अधिक कच्चे माल और अन्य चीजों की ताबड़तोड़ खरीद कर रही हैं. ऐसे में वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला पर बहुत अधिक दबाव बढ़ गया है. इसके अलावा चीजों की कमी भी हो रही है और उनके दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं. ऐसी स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की आशंका बढ़ गयी है. यदि जल्दी ही इस अफरातफरी पर काबू नहीं पाया गया, तो महामारी और मंदी से जूझती अर्थव्यवस्था का संकट गहरा हो जायेगा. लोहा, तांबा, गेहूं, सोयाबीन से लेकर प्लास्टिक और कार्डबोर्ड की चीजों की कमी हो गयी है. जानकारों के अनुसार, कंपनियों का मानना है कि कई देशों में महामारी पर नियंत्रण होने की वजह से बाजार में तैयार माल की बढ़ी मांग अगले साल तक बरकरार रहेगी. सो, वे पहले से ही बड़ी मात्रा में भंडारण कर रही हैं. चूंकि इनकी आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं हो पा रही है और यातायात में भी मुश्किलें आ रही हैं, तो कीमतें में बढ़ोतरी भी स्वाभाविक है. इसका एक सीधा असर तो तैयार माल के थोक और खुदरा दामों पर भी होगा. इसके संकेत भी दिखने लगे हैं. इससे एक दूसरी चिंता यह पैदा हो गयी है कि महंगाई बढ़ने से बाजार में मांग भी घट सकती है. उल्लेखनीय है कि अर्थव्यवस्था के समुचित विकास के लिए उत्पादन, मांग, दाम, रोजगार और आमदनी में संतुलन होना जरूरी है. इस स्थिति के पैदा होने के अनेक कारण हैं. एक तो कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अस्त-व्यस्त कर दिया और इसका प्रकोप अभी भी पूरी तरह से थमा नहीं है. मार्च में स्वेज नहर में एक बड़े जहाज के कई दिनों तक फंसे रहने के चलते सामानों की ढुलाई बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई थी. अमेरिका समेत कई देशों में सूखे की वजह से कृषि क्षेत्र पर असर पड़ा. तेल, अन्य खनिजों और धातुओं की कीमतों में बड़े उतार-चढ़ाव देखे गये. अभी भारत में महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है, जिससे बंदरगाहों की गतिविधियां शिथिल हुई हैं. इन कारकों से श्रम और पूंजी की उपलब्धता में अनिश्चितता पैदा हुई है. मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने और बाजार में पूंजी मुहैया कराने के लिए ब्याज दरों की समीक्षा का दबाव भी बढ़ रहा है. महामारी से अधिक प्रभावित हर देश को राहत के लिए भी धन मुहैया कराना पड़ा है. भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है. अप्रैल में थोक मुद्रास्फीति लंबे समय में सबसे अधिक रही थी. हालांकि खुदरा मुद्रास्फीति में कुछ कमी आयी है, पर यह मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के दाम घटने का नतीजा है. यदि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ताबड़तोड़ खरीद जारी रही, तो महंगाई और बढ़ेगी. चूंकि कुछ महीनों में स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है, इसलिए इस संबंध में ठोस नीतिगत पहल जरूरी है.

एक साल में 21 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल!

मुंबई। एजेंसी

ट्रोल-डीजल की कीमतें All Time High पर हैं, यानी इससे पहले पेट्रोल-डीजल इतना महंगा कभी नहीं हुआ। मुंबई में पेट्रोल पहली बार 99 रुपये के पार पहुंचा है. ऐसे ही दाम बढ़ते रहे तो आने वाले कुछ दिनों में ये 100 रुपये के पार भी जाएगा। पेट्रोल-डीजल की कीमतें अब एक दिन छोड़कर बढ़ रही हैं, बीते कई दिनों से ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। हालांकि पेट्रोल-डीजल की कीमतों का आलम ये है कि ये अपने All Time High यानी महंगाई के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका है। मुंबई में पेट्रोल का रेट 99 रुपये के पार जा चुका है।

मई में अबतक 10 बार बढ़े दाम

4 मई से लगातार 4 दिन तक पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े थे, जबकि चुनावों की वजह से इसके पहले 18 दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में शांति छाई रही थी। मई में पेट्रोल और डीजल अबतक 10 बार महंगा हो चुका है. मई में अबतक दिल्ली में पेट्रोल के रेट 2.45 रुपये बढ़ चुके हैं, जबकि डीजल इस महीने 2.78 रुपये महंगा हो चुका है।

मार्च, अप्रैल में सस्ता हुआ था पेट्रोल-डीजल

इसके पहले आम लोगों को महंगे पेट्रोल-डीजल से 15 अप्रैल को थोड़ी राहत मिली थी। अप्रैल में एक और मार्च के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन बार कटौती हुई थी। 15 अप्रैल से पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आखिरी बार बदलाव 30 मार्च 2021 को हुआ था। तब दिल्ली में पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 23 पैसे सस्ता हुआ था। मार्च महीने पेट्रोल 61 पैसे सस्ता हुआ था और डीजल के दाम 60 पैसे घटे थे. मार्च महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 बार कटौती की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कमजोरी थी।

मई में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

दिल्ली में पेट्रोल आज 92.85 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। बाकी शहरों जैसे मुंबई पेट्रोल 99.14 रुपये है, कोलकाता में पेट्रोल 92.92 रुपये है. और चेन्नई में पेट्रोल 94.54 रुपये पर बिक रहा है।

मई में पेट्रोल और डीजल 10 बार महंगा हो चुका है। इसके पहले फरवरी में पेट्रोल-डीजल के रेट में 16 बार बढ़ोतरी हुई थी। इससे पहले जनवरी में रेट 10 बार बढ़े थे। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 2.59 रुपए और डीजल में 2.61 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। साल 2021 में अब तक तेल की कीमतें 36 दिन बढ़ाईं गई हैं. इस दौरान पेट्रोल 9.14 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है. 1 जनवरी को पेट्रोल का भाव 83.71 रुपये था, आज 92.85 रुपये प्रति लीटर है. इसी तरह दिल्ली में 1 जनवरी से लेकर आज तक डीजल 9.64 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है. 1 जनवरी को दिल्ली में डीजल का दाम 73.87 रुपये प्रति लीटर था, आज 83.51 रुपये है।

1 साल में पेट्रोल 21 रुपये महंगा हुआ

अगर आज की कीमतों की तुलना ठीक साल भर पहले की कीमतों से करें तो 19 मई 2020 को दिल्ली में पेट्रोल का रेट 71.26 रुपये प्रति लीटर था, यानी साल भर में पेट्रोल 21.59 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। डीजल भी 19 मई 2020 को 69.39 रुपये प्रति लीटर था, यानी डीजल भी साल भर में 14.12 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल के बाद अब आज डीजल की नई कीमतों पर एक नजर डाल लेते हैं। मुंबई में डीजल 90.71 रुपये हो गया है। दिल्ली में डीजल 83.51 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। कोलकाता में डीजल 86.35 रुपये पर बिक रहा है और चेन्नई में डीजल का रेट 88.34 रुपये है।

केंद्र और राज्य सरकारें वसूलती हैं भारी टैक्स

पेट्रोल की कीमतों में 60 परसेंट हिस्सा सेंट्रल एक्साइज और राज्यों के टैक्स का होता है, जबकि डीजल में ये 54 परसेंट होता है। पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 32.90 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल पर 31.80 रुपये प्रति लीटर है. पेट्रोल डीजल की कीमतों में आमतौर पर रोज बदलाव होता है, ये कीमतें बेंचमार्क अंतरराष्ट्रीय क्रूड कीमतों और फॉरेन एक्सचेंज रेट के आधार पर तय होती हैं।

मार्च के बाद पहली बार कच्चा तेल 70 डॉलर के पार

नई दिल्ली । एजेंसी

कच्चे तेल में मंगलवार को उछाल आया। इस साल मार्च के बाद पहली बार इसका भाव 70 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने से कच्चे तेल की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इस वजह से इसकी कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। ब्रिटेन में सोमवार से ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं. यूरोपीय देशों में भी धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं। उधर, अमेरिका में कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है। न्यूयॉर्क में उन लोगों के लिए मास्क लगाना जरूरी नहीं है, जिन्हें टीका लग चुका है। इससे कच्चे तेल की मांग बढ़ने की उम्मीद है। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 70 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया। फिर थोड़ी देर बाद यह 47 सेंट यानी 0.7 फीसदी चढ़कर 69.93 डॉलर प्रति बैरल चल रहा था। इस साल 15 मार्च के बाद पहली बार क्रूड ने 70 डॉलर प्रति बैरल का स्तर पार किया है। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडियट (WTI) भी 45 सेंट चढ़कर 66.72 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। जानकारों का कहना है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था खुल रही हैं. हालांकि, एशिया में अब भी कोरोना से हालात गंभीर बने हुए हैं। इस वजह से क्रूड की कीमतों में ज्यादा तेजी नहीं आ रही है। इस हफ्ते के अंत में अमेरिका में क्रूड सप्लाई के आंकड़े जारी होंगे। अमेरिका में क्रूड इनवेंट्री में 17 लाख बैरल की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

कमजोर हाजिर मांग से कच्चा तेल वायदा कीमतों में गिरावट

नई दिल्ली । एजेंसी

कारोबारियों द्वारा अपने सौदों के आकार को घटाने के कारण वायदा कारोबार में बुधवार को कच्चा तेल की कीमत 50 रुपये की गिरावट के साथ 4,749 रुपये प्रति बैरल रह गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कच्चातेल के जून डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 50 रुपये अथवा 1.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,749 रुपये प्रति बैरल रह गई जिसमें 4,403 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कमजोर हाजिर मांग के बीच व्यापारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से वायदा कारोबार में कच्चातेल कीमतों में हानि दर्ज हुई। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में वेस्ट टैक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का दाम 1.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 64.58 डालर प्रति बैरल रह गया। जबकि, वैश्विक मानक माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड का दाम 1.24 प्रतिशत घटकर 67.86 डालर प्रति बैरल रह गया।

डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे और मजबूत खुला

नई दिल्ली। एजेंसी

विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज बुधवार को मजबूती के साथ खुला। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की मजबूती के साथ 73.02 रुपये के स्तर पर खुला। वहीं, मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे की मजबूती के साथ 73.04 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर में कारोबार काफी समझदारी से करने की जरूरत होती है, नहीं तो निवेश पर असर पड़ सकता है।

जानिए पिछले 5 दिनों के रुपये का क्लोजिंग स्तर

■मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे की मजबूती के साथ 73.04 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। ■सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की मजबूती के साथ 73.21 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। ■शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे की मजबूती के साथ 73.28 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। ■बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की कमजोरी के साथ 73.42 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। ■मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे की मजबूती के साथ 73.34 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।

आजादी के समय रुपये का स्तर

एक जमाना था जब अपना रुपया डॉलर को जबरदस्त टक्कर दिया करता था। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो डॉलर और रुपये का दाम बराबर का था। मतलब एक डॉलर बराबर एक रुपया था। तब देश पर कोई कर्ज भी नहीं था। फिर जब 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो सरकार ने विदेशों से कर्ज लेना शुरू किया और फिर रुपये की साख भी लगातार कम होने लगी। 1975 तक आते-आते तो एक डॉलर की कीमत 8 रुपये हो गई और 1985 में डॉलर का भाव हो गया 12 रुपये। 1991 में नरसिम्हा राव के शासनकाल में भारत ने उदारीकरण की राह पकड़ी और रुपया भी धड़ाम गिरने लगा।

डिमांड सप्लाई तय करता है भाव

करेंसी एक्सपर्ट के अनुसार रुपये की कीमत पूरी तरह इसकी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी इस पर असर पड़ता है। हर देश के पास उस विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, जिसमें वो लेन-देन करता है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा की चाल तय होती है। अमरीकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है और ज्यादातर देश इंपोर्ट का बिल डॉलर में ही चुकाते हैं।

अगर कोरोना से प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी की हुई है मौत तो उसके नॉमिनी को मिलेंगे 7 लाख रुपये

नई दिल्ली। एजेंसी

पूरा देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। बड़ी संख्या में लोगों की जान भी इस बिमारी की वजह से जा रही है। ऐसे परिवारों पर संकट अचानक बढ़ गया है। पीएफ अकाउंट होल्डर को 7 लाख रूपये तक का फ्री इंश्योरेंस मिलता है। ऐसे में अगर किसी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य 7 लाख रूपये का डेथ क्लेम कर सकते हैं। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले कर्मचारी के परिवार के सदस्य या नॉमिनी भी इस इंश्योरेंस के तहत डेथ क्लेम कर सकता है।

इन्हें मिलता है फायदा

सीबीटी ने अधिकतम बीमा राशि 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने के लिए सितंबर 2020 में ईडीएलआई, 1976 के पैराग्राफ 22 (3) में संशोधन को मंजूरी दी थी। इस संशोधन का मकसद योजना से जुड़े उन सदस्यों के परिवार और आश्रितों को राहत प्रदान करना है, जिनका सेवा में रहते दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो जाता है। सीबीटी की मार्च 2020 में हुई बैठक में ईपीएफओ न्यासियों ने न्यूनतम 2.5 लाख रुपये का निश्चित लाभ उस मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को देने की सिफारिश की, जिनका निधन सेवा के दौरान हो जाता है। अगर किसी कर्मचारी की डेथ कोरोना की वजह से हुई है तो वह भी इसके लिए क्लेम कर सकता है।

EDLI के तहत यह पैसा पीएफ अकाउंट होल्डर के नॉमिनी को मिलता है। लेकिन अगर अकाउंट होल्डर ने किसी को अपना नॉमिनी नहीं बनाया है तो कर्मचारी की पत्नी, बच्चे भी पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं।

कैसे होगा कैलकुलेशन

EDLI की नई अपडेट के अनुसार आखिरी 12 माह की बेसिक सैलरी का 35 गुना ₹ बोनस कर्मचारी के परिवार या नॉमिनी को दिया जाता है। मान लीजिए किसी की सैलरी 15,000 रुपये है तो इसका 35 गुना होगा 5,25,000 रुपये और इसमें अगर 1,75,000 और जोड़ दें तो यह 7 लाख रुपये हो जाएगा। पहले इस स्कीम के जरिए सिर्फ 6 लाख रुपये ही मिलता था। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि कर्मचारी के पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू करते ही वह इसका पात्र बन जाता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती।

कंपनियों का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अप्रैल में दोगुना बढ़कर 2.51 अरब डालर पर पहुंचा

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय कंपनियों की ओर से विदेशों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश चालू वित्त वर्ष के पहले महीने अप्रैल में पिछले साल इसी माह की तुलना में दुगुने से भी अधिक बढ़कर 2.51 अरब डालर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। एक साल पहले यह आंकड़ा 1.21 अरब डालर था।

भारतीय कंपनियों ने अप्रैल में विदेशों में कुल 2.51 अरब डालर के प्रत्यक्ष पूंजी निवेश (ओएफडीआई) की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें से 1.75 अरब डालर कर्ज के रूप में, 42.14 करोड़ डालर शेयर पूंजी और 33.31 करोड़ डालर गारंटी के तौर पर निवेश किया गया। आरबीआई के अप्रैल 2021 के ओएफडीआई आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। मार्च 2021 में भारत का ओएफडीआई 1.99 अरब डालर का निवेश किया। अप्रैल में टाटा स्टील ने सिंगापुर में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी में एक अरब डालर का निवेश किया। वहीं इंटरग्लोब एंटरप्राइजिज प्रा. लि. ने ब्रिटेन स्थित संयुक्त उद्यम में 14.56 करोड़ डालर का निवेश किया। रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड ने ब्रिटेन में पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई में 7.85 करोड़ डालर के निवेश की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस ब्रांड के साथ मिल कर ब्रिटेन, सिंगापुर, यूएई और अमेरिका में पूर्ण स्वामित्व और संयुक्त उद्यमों में 9.15 करोड़ डालर का निवेश किया। इसके अलावा वेरोक इंजीनियरिंग ने नीदरलैंड स्थित इकाई में 6.55 करोड़ डालर और मदरसन सुमी सिस्टम्स ने यूएई स्थित इकाई में 4.17 करोड़ डालर का निवेश किया।

कोविड खर्च, ईंधन के दाम बढ़ने, आनलाइन डिलीवरी से महंगाई बढ़ेगी, मांग प्रभावित होगी : रिपोर्ट

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

स्वास्थ्य खर्चे में तेज वृद्धि, ईंधन के बढ़ते दाम और वस्तुओं की आनलाइन डिलिवरी से जहां एक तरफ मुद्रास्फीति पर काफी दबाव पड़ेगा वहीं दूसरी तरफ दूसरी तरफ उपभोक्ताओं की दूसरी तरह की मांग की क्षमता कम होगी। इससे वृद्धि की संभावनाएं प्रभावित होंगी, क्योंकि आर्थिक वृद्धि अभी भी खपत आधारित मांग पर निर्भर है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में समूह की प्रमुख आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष ने एक नोट में यह भी कहा है कि अप्रैल माह के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति के मार्च के 5.52 प्रतिशत से घटकर 4.29 प्रतिशत रहना भ्रमित करने वाला है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुद्रास्फीति के आंकड़े प्राथमिक तौर पर खाद्य वस्तुओं के नरम पड़ते दाम की वजह से है जबकि इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र संबंधी मूल मुद्रास्फीति बढ़कर 6.4 प्रतिशत पर पहुंच गई।

महामारी के पूरे देश में फैलने के साथ हमें मुख्य मुद्रास्फीति के आंकड़ों से आगे देखने की जरूरत है। ग्रामीण मूल मुद्रास्फीति अप्रैल माह में बढ़कर 6.4 प्रतिशत पर पहुंच गई और यह मई में और बढ़ सकती है। महामारी के कारण स्वास्थ्य पर बढ़ते खर्च का ग्रामीण इलाकों में अर्थपरक प्रभाव होगा।

खुदरा मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में शामिल स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुवार मुद्रास्फीति पर यदि गौर किया जाये तो गैर-संस्थागत दवाओं, एक्स-रे, ईसीजी, नैदानिक परीक्षण आदि की मुद्रास्फीति माह-दर- माह बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर समग्र खुदरा मूल्य सूचकांक अप्रैल में कम हुआ है, इस दौरान खाद्य सीपीआई में गिरावट आई है लेकिन जब खाद्य वस्तुओं की महंगाई की समग्र सीपीआई से तुलना की जाती है तो खाद्य सीपीआई में जो गिरावट दिखती है वास्तव में यह उतनी तेज नहीं है। इसी प्रकार ईंधन और स्वास्थ्य के मामले में मुद्रास्फीति की वृद्धि अधिकतम है लेकिन मजे की बात यह है कि मूल सीपीआई कि 0.57 प्रतिशत घटा है जबकि संबंधित वर्ग में यह 18 अंक बढ़ा है। घोष के मुताबिक मूल्य दबाव का आकलन करने के लिये तीन अहम बिंदु हैं। इनमें स्वास्थ्य, ईंधन मूल्य और उपभोक्ता जिंसों के बढ़ते दाम शामिल हैं। महामारी के चलते स्वास्थ्य खर्च जो कि समग्र मुद्रास्फीति में इस समय पांच प्रतिशत है वह आगे 11 प्रतिशत पर पहुंच सकता है।

इस स्थिति का दूसरे उपभोकता सामानों की खपत पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर दूसरे सामानों की खपत में कटौती हो सकती है। वहीं ईंधन के बढ़ते दाम का भी स्वास्थ्य व्यय को छोड़कर अन्य खपतों पर प्रभाव पड़ सकता है। घोष के मुताबिक ऐसी स्थिति से बाहर निकलने का यही रास्ता है कि पेट्रोल, डीजल पर कर दरों को तर्कसंगत बनाकर इनके दाम में कटौती की जाये। अन्यथा विवेक से होने वाला व्यय पीछे धकेला जाता रहेगा और गैर-विवेकाधीन व्यय बढ़ता रहेगा। दूसरी तरफ आनलाइन डिलीवरी प्लेटफार्म का इसतेमाल बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आनलाइन कीमतों को संज्ञान में नहीं लेता है यदि वह आनलाइन मूल्यों पर भी विचार करे तो खुदरा मुद्रास्फीति पर 10 से 15 आधार अंक का प्रभाव पड़ सकता है।

यूपी में कोरोना ड्यूटी में लगे इमरजेंसी वाहनों को रिलांयस पेट्रोल पंप से रोजाना 50 लीटर डीजल-पेट्रोल फ्री

लखनऊ। एजेंसी

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक ओर जहां योगी सरकार युद्धस्तर पर प्रयास करती नजर आ रही है, वहीं देश और प्रदेश के हर सुख-दुख में साथ खड़ा रहने वाले रिलायंस ग्रुप भी यूपी के लोगों और योगी सरकार की बड़ी मदद करता नजर आ रहा है। इसके तहत रिलांयस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड ने मंगलवार से रिलायंस पेट्रोल पंप पर कोरोना ड्यूटी में लगे एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सप्लाई सेवा में लगे इमरजेंसी वाहनों को फ्री में रोजाना 50 लीटर डीजल-पेट्रोल देने का ऐलान किया है। शासन-प्रशासन द्वारा मुहैया कराई गई इमरजेंसी वाहनों की सूची में शामिल हर वाहन को आगामी 30 जून तक फ्री में 50 लीटर डीजल-पेट्रोल देना शुरू कर दिया गया है।

दरअसल, कोरोना संकट के दौरान एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट संस्थान के रूप में रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड (RBML) ने कोविड-19 के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में राष्ट्र की सेवा में अपना कर्तव्य निभाने का निर्णय लिया है। इस दिशा में सभी RBML रिटेल आउटलेट यानी कि रिलायंस पेट्रोल पंप जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत आपातकालीन सेवा में लगे वाहनों को प्रतिदिन 50 लीटर डीजल-पेट्रोल मुफ्त में दिया जाएगा। यह पहल 30 जून तक जारी रहेगी। फिलहाल RBML को शासन द्वारा आंक्सीजन सप्लाई में लगे 69 टैंकरों की सूची मुहैया कराई गई है, लेकिन एंबुलेंस और अन्य इमरजेंसी वाहनों समेत करीब 1500 वाहन होने की बात कही जा रही है।

6 महीने में पहली बार होगी जीएसटी की बैठक, इन मुद्दे पर होगा जोर

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 28 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक की अगुवाई करेंगी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक 6 महीने के अंतराल के बाद हो रही है। पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने की मांग की थी।

सीतारमण के कार्यालय ने शनिवार को एक ट्वीट में इस बैठक के बारे में जानकारी दी। इसमें कहा गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 28 मई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 43वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगी। इसमें वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे।

6 महीने में पहली बैठक

जीएसटी काउंसिल की बैठक 6 महीने बाद हो रही है। इससे पहले इस हफ्ते पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सीतारमण को पत्र लिखकर राज्यों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा के वास्ते तत्काल जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने की मांग की थी। वित्त वर्ष 2022 में राज्यों के लिए 1.56 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा तय किया गया है। केंद्र सरकार के अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में 156164 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है। मित्रा का कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर से मुआवजे की राशि पूर्व अनुमान से कहीं अधिक होगी।

वित्त वर्ष 2021 में जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र ने राज्यों को 1.1 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया था। वित्त मंत्रालय ने मार्च में कहा था कि वित्त वर्ष 2021 के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का 63,000 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा लंबित है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का कहना था कि कोरोना महामारी के मद्देनजर कुछ मुद्दों पर तुरंत चर्चा की जरूरत है। इसमें यह मुद्दा भी शामिल है कि क्या हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क, दस्तानों, पीपीई किट्स, टेंपरेटर नापने वाले इक्विपमेंट, ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर और दूसरे सामान पर जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए। जीएसटी की पिछली बैठक 5 अक्टूबर को हुई थी।

आयातकों को सामान पर रियायती शुल्क पाने के लिये पहले करना होगा सूचितः सीबीआईसी

नयी दिल्ली। एजेंसी

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि आयातकों को रियायती शुल्क दरों का लाभ उठाने के लिये आयात किये जाने वाले सामान, उसकी अनुमानित मात्रा और मूल्य के बारे में सीमा शुल्क अधिकारियों को पहले से सूचना देनी होगी। सीबीआईसी ने आयातकों की सुविधा के लिये सीमा शुल्क (रियायत शुल्क दर पर सामान का आयात) नियमों में संशोधन किया है। इसमें उस पूरी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जिसके तहत घरेलू स्तर पर उत्पादन अथवा सेवायें देने के लिये आयात किये जाने वाले सामान पर रियायती दर से शुल्क का लाभ उठाया जा सकता है। इसमें जो एक प्रमुख बदलाव किया गया है वह यह कि आयातित सामान को अब 'जॉब वर्क' के लिये बाहर भेजा जा सकता है। इस सुविधा के बिना पहले उद्योगों को काफी परेशानी होती रही है। खासतौर से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को इसका लाभ मिलेगा जिनके पास खुद की पूरी विनिर्माण सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्हें कुछ न कुछ काम बाहर से कराना होता है।

यहां तक कि ऐसे आयातक जिनके पास कोई विनिर्माण कारखाना नहीं है वह भी आयातित सामान की रियायती शुल्क दर का लाभ उठा सकते हैं। वह रियायत दर पर माल का आयात कर उसपर बाहर से जॉब वर्क कराकर उसे अंतिम रूप से तैयार कर सकते हैं। हालांकि, सोना, आभूषण, कीमती धातुओं और धातुओं के कारोबार को इससे अलग रखा गया है। सीबीआईसी ने जारी सर्कुलर में कहा है, ''कोई भी आयातक रियायती शुल्क दर पर सामान का आयात करना चाहता है उसे ऐसे सामान की संबंधित क्षेत्र के सीमा शुल्क अधिकारी को एकबारगी अग्रिम सूचना देनी होगी। आयातक को आयातक के परिसर का नाम और पता, उसके जॉब वर्कर यदि कोई हों तो, आयातक अथवा जॉब वर्कर के परिसर में विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामान की प्रकृति और उसका ब्यौरा तथा आयातित सामान के इस्तेमाल के बाद दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी देनी होगी।'' सीबीआईसी ने कहा है कि आयातक को आयात करने से पहले सामान की मात्रा उसकी अनुमानित कीमत, शुल्क छूट अधिसूचना और उसका क्रमांक नंबर, मिलने वाली शुल्क छूट और जिस बंदरगाह पर माल पहुंचना है उसके बारे में पहले से सूचित करना होगा। यह सूचना ई-मेल के जरिये प्रत्येक आयात के बजाय एकीकृत आधार पर एक साल तक की अवधि के लिये दी जा सकती है। आयातकों को और भी कई तरह की सुविधायें इसमें दी गई हैं। सीबीआईसी ने कहा है कि व्यापार और उद्योग की मांग पर इन बदलावों को किया गया है। वैश्विक व्यवहारों में आते बदलावों को देखते हुये उनकी जरूरतों के मुताबिक यह कदम उठाये गये हैं।

ई-वे बिल फास्टैग से जुड़ा

जीएसटी अधिकारी अब वाणिज्यिक वाहनों की आवजाही का सही समय जान सकेंगे

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों को अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही के वास्तविक समय की जानकारी भी हासिल होगी। वाणिज्यिक वाहनों द्वारा लिये जाने वाले ई-वे बिल प्रणाली को अब फास्टैग और आरएफआईडी के साथ जोड़ दिया गया है। इससे वाणिज्यिक वाहनों पर सटीक नजर रखी जा सकेगी और जीएसटी चोरी का पता चल सकेगा।

जीएसटी अधिकारियों की ई-वे बिल मोबाइल एप में यह नया फीचर जोड़ दिया गया है। इसके जरिये वह ई- वे बिल का वास्तविक ब्योरा जान सकेंगे। इससे उन्हें कर चोरी करने वालों को पकड़ने और ई-वे बिल प्रणाली का दुरुपयोग करने वालों को पकड़ने में मदद मिलेगी।

जीएसटी कर के तहत 28 अप्रैल, 2018 से व्यापारियों और ट्रांसपोटरों को पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य का सामान की अंतरराज्यीय बिक्री और खरीद पर ईवे-बिल बनाना और दिखाना अनिवार्य है। ई-वे बिल प्रणाली में रोजाना औसतन 25 लाख मालवाहक वाहनों की आवाजाही देश के 800 से अधिक टोल नाकों से होती है।

इस नयी प्रक्रिया से अधिकारी उन वाहनों की रिपोर्ट देख सकेंगे जिन्होंने पिछले कुछ मिनटों के दौरान बिना ई-वे बिल के टोल नाकों को पार किया है। साथ ही किसी राज्य के लिए आवश्यक वस्तु ले जा रहे वाहनों के टोल को पार करने की रिपोर्ट को भी देखा जा सकेगा। कर अधिकारी वाहनों के संचालन की समीक्षा करते समय इन रिपोर्टों का उपयोग कर सकेंगे। एमआरजी एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा, ''वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही और वस्तुओं पर नजर रखने के लिए वाहनों की सटीक जानकारी से कर चोरी रोकने में मदद करेगी।''

पिछले महीने सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि मार्च 2021 तक यानी पिछले तीन साल के दौरान देश में कुल 180 करोड़ इवे-बिल जारी किये गए। जिसमे से कर अधिकारियों द्वारा केवल सात करोड़ इवे-बिल की ही पुष्टि की जा सकी। सरकार के आंकड़ों के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक में अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए सबसे अधिक ई-वे बिल सृजित किए जाते हैं।

भारत की इकनॉमी के बारे में आरबीआई के बुलेटिन में दी गई है यह बड़ी जानकारी

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत के बैंकिंग नियामक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोरोनावायरस के दूसरे चरण में समग्र डिमांड पर काफी असर पड़ा है। इसकी तुलना में अभी आपूर्ति अधिक प्रभावित नहीं हुई है। भारत के केंद्रीय बैंक का मानना है कि 1 साल पहले की तुलना में भारत का आर्थिक संकट इतना गंभीर नहीं है। सोमवार को देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या में कमी देखी गई, लेकिन महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या 4000 के पार बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण के आंकड़े भरोसे के लायक नहीं हैं क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और वहां टेस्टिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

भारत की इकनॉमी पर असर

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन में कहा, 'कोरोना संकट के दूसरे चरण में मांग में आई कमी की वजह से अर्थव्यवस्था की दिक्कत बढ़ गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन की वजह से डिमांड पर असर पड़ा है। इसके साथ ही लोगों के बचत करने की बढ़ती प्रवृत्ति और रोजगार के मौके छिन जाने की वजह से भी मांग पर असर पड़ा है। इन्वेंटरी जमा होने की वजह से समग्र सप्लाई पर कम असर पड़ा है।'

बहुत असर नहीं पड़ेगा

आपने बुलेटिन में RBI ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण में नए केस की संख्या में कमी आई है और इसका चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में आर्थिक गतिविधियों पर अधिक असर पड़ने की आशंका नहीं है। भारत के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस समय इस बारे में भरोसे से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना लग रहा है कि 1 साल पहले की तुलना में इस समय स्थिति गंभीर नहीं है।

वर्क फ्रॉम होम का बढ़ा चलन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन में कहा कि कई राज्यों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन किया गया है। इसके साथ ही लोगों ने work-from-home करना शुरू किया है। देश में ऑनलाइन डिलीवरी बढ़ी है, ई-कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट का भी प्रयोग बढ़ रहा है।

कर्ज लेने वालों को राहत

इस महीने की शुरुआत में आरबीआई ने कर्ज देने वाले संस्थानों को बैड लोन की बढ़ती समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए कई उपाय की घोषणा की थी। इसके साथ ही उधार लेने वाले कुछ लोगों को आरबीआई ने अपना कर्ज चुकाने के लिए अधिक समय देने की भी घोषणा की थी।

कोविड-19 महामारी के समय में प्लास्टिकः रक्षक या प्रदूषक?

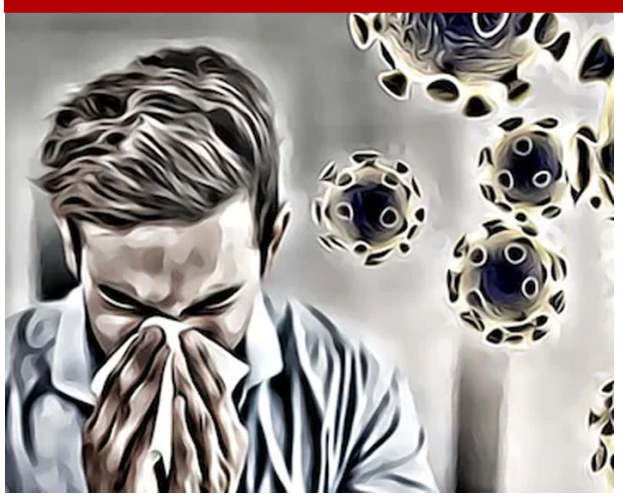

■कोविड-19 महामारी ने हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक की अपरिहार्य भूमिका पर फिर से जोर दिया ■कोविड-19 के दौरान अस्थाई बदलाव सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक से उपभोक्ताओं का व्यवहार बदला ■ स्वचालित अपशिष्ट प्रबंधन और उत्पाद नवाचार से पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त हो सकती है।

आईपीटी नेटवर्क

विशेष संवाददाता। कोविड-19 महामारी ने हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक की अपरिहार्य भूमिका पर फिर से जोर दिया है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) और अन्य एक बार उपयोग वाले चिकित्सा उपकरणों के साथ-साथ पैकेजिंग समाधानों के संदर्भ में प्लास्टिक अपने अंतर्निहित गुणों के कारण फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए एक जीवन रक्षक के रूप में उभरा है। हालांकि, इस अभूतपूर्व संकट के दौरान प्लास्टिक के उपयोग और अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि के बीच अंधाधुंध कूड़ेदान और कुप्रबंधन के कारण प्लास्टिक को बुरा प्रदूषक माना गया है। क्या महामारी के समय में प्लास्टिक सार्वजनिक स्वास्थ्य के रक्षक या पर्यावरण के प्रदूषक के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्लास्टिक की उपयोगिताओं और सीमाओं के साथ-साथ इसके प्रबंधन या कुप्रबंधन, और भविष्य को को ध्यान में रखते हुए, एक समान मूल्यांकन से पता चलता है कि उपभोक्ताओं का गैर-जिम्मेदार व्यवहार और खराब जागरूकता, संग्रह -संचालन, प्रमुख चालकों के रूप में वित्तीय बाधाएं कुप्रबंधन की ओर ले जाती हैं। प्लास्टिक को पर्यावरण के एक बुरे प्रदूषक में बदल देती हैं। प्लास्टिक एक रक्षक हो सकता है यदि इसे ठीक से प्रबंधित किया जाए। उसकी कमी, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति के मामले में सर्क्यूलर इकोनॉमी रणनीतियों द्वारा पूरक किया जाए। इस तरह पर्यावरण में लिकेज को रोका जा सके।

कोविड-19 वैश्नविक महामारी के दौर में पीपीई की आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा के लिए, दुनिया भर में कई परिशोधन तकनीकों को अपनाया गया है ताकि सिस्टम के भीतर सर्क्यूलर इकोनॉमी को प्राथमिकता देने के लिए उनके प्रभावी पुनर्संसाधन को सुनिश्चित किया जा सके। जागरूकता पैदा करने के लिए उपभोक्ताओं की शिक्षा के साथ-साथ सुरक्षित प्रथाओं और टिकाऊ तकनीकी समाधानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले नीतिगत दिशानिर्देश प्लास्टिक को उच्च उपयोगिता वाले प्रदूषक से प्लास्टिक को रोकने के लिए समय की आवश्यकता है।

गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोनावायरस 2 (SARS-CoV-2) के कारण वैश्विक चिंता की महामारी, कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) के साथ, पूरी दुनिया एक ऐसी जीवन शैली का गवाह बन गई है जो न्यू नार्मल होती जा रही है। SARS-CoV-2 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलने के लिए जाना जाता है। कोविड 19 संकट ने हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक की अपरिहार्य भूमिका पर फिर से जोर दिया है। महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा में प्लास्टिक ने बहुत योगदान दिया है। एहतियाती उपायों के रूप में कोविड-19 के प्रसार से लडने के लिए वायरस के संक्रमण से बचने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन , सोशल डिस्टेंस, ट्रेवलिंग और सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध, ज्यादातर प्लास्टिक-आधारित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहनने के साथ-साथ हैंड सैनिटाइज़र के लगातार उपयोग के अलावा, फेस मास्क आम नागरिकों के लिए सुरक्षात्मक मेडिकल सूट, एप्रन, गाउन, फेस शील्ड, सर्जिकल मास्क, और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए अन्य पीपीई के लिए दस्ताने अपनाया गया है। प्लास्टिक बहुमुखी प्रतिभा के साथ वजन अनुपात और स्थायित्व के लिए उत्कृष्ट शक्ति को एकीकृत करता है। इन गुणों के कारण, प्लास्टिक कुछ सर्जिकल ऑपरेशन और ट्रांसप्लांट में उपयोग के साथ-साथ एकल-उपयोग चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों और पैकेजिंग में प्रमुख अनुप्रयोगों के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपूरणीय हैं। इसके अलावा, प्लास्टिक पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए एकदम सही सामग्री के रूप में विकसित हुए हैं क्योंकि वे हल्के, लचीले और अत्यधिक टिकाऊ होते हैं।

पैकेजिंग एप्लिकेशन दुनिया भर में प्लास्टिक के सबसे व्यापक उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं। महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन शॉपिंग और टेकअवे सेवाओं पर निर्भरता के साथ उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव के कारण प्लास्टिक आधारित पैकेजिंग वस्तुओं की मांग में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक (एसयूपी) शामिल हैं।

कई देशों में प्रचलित प्रतिबंध या महामारी के दौरान प्लास्टिक की मांग में वृद्धि मुख्य रूप से पीपीई और पैकेजिंग सामग्री के निर्माण के कारण हुई है। अधिकांश पीपीई पॉलीयुरेथेन (पीयू), पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी), पॉली कार्बोनेट (पीसी), कम घनत्व वाले पॉलीइथाइलीन (एलडीपीई), पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) जैसे पॉलिमर से बने होते हैं, जबकि पैकेजिंग सामग्री में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक में मुख्य रूप से उच्च होते हैं। -घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई), कम घनत्व पॉलीथीन (एलडीपीई), पॉलीस्टीरिन (पीएस), पॉलीथीन टेरेफेथलेट (पीईटी), इत्यादि है। इनमें से, पीएस और एलडीपीई शायद ही कभी पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक होते हैं, पीईटी और एचडीपीई व्यापक रूप से पुनर्नवीनीकरण होते हैं, जबकि पीवीसी और पीपी अक्सर पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जाता है।

महामारी के दौरान पीपीई और पैकेजिंग सामग्री के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के उपयोग और पुनर्चक्रण को दर्शाया गया है। प्लास्टिक मानव जाति के लिए समृद्धि लाता है, लेकिन सीमाएं और समस्याएं भी हैं। क्योंकि उनका प्रमुख लाभ मुख्य समस्या बन जाता है। पारंपरिक सामग्रियों की तुलना में सस्ता होने के कारण, प्लास्टिक डिस्पोजेबल के साथ असंख्य अनुप्रयोगों में एकल-उपयोग की अनुमति देता है। इसे स्वच्छता को प्राथमिकता देने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा एक प्रमुख लाभ के रूप में माना जाता है। यद्यपि प्लास्टिक को नोवल कोरोनवायरस की दृढ़ता के संबंध में अन्य सामग्रियों की तुलना में बेहतर विकल्प नहीं बताया गया है। इससे महामारी के दौरान चिकित्सा और गैर-चिकित्सा दोनों अनुप्रयोगों के लिए प्लास्टिक-आधारित वस्तुओं के उपयोग और निपटान में वृद्धि हुई है। खतरनाक कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट जिसमें संक्रमित प्लास्टिक-आधारित पीपीई और अन्य डिस्पोजेबल आइटम जैसे कोविड-19 अस्पताल, कोरेंटाइन सुविधाएं, नियंत्रण क्षेत्र, गैर-प्रभावित स्रोतों से समान गैर-संक्रमित आइटम उत्पन्न होते हैं।

महामारी में कचरा प्रबंधन बड़ी चुनौती

महामारी के बीच चिकित्सा उत्पादों और पैकेजिंग की बढ़ती मांग के साथ एसयूपी और प्लास्टिक-आधारित पैकेजिंग सामग्री के बढ़ते उपयोग ने दुनिया भर में प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में काफी वृद्धि की है। इस प्रकार, महामारी ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के मामले में एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती पेश की है। अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं को आम तौर पर सामान्य परिस्थितियों में अपशिष्ट मात्रा और संरचना में मध्यम बदलाव के साथ स्थिर-राज्य संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा, महामारी से प्रेरित लॉकडाउन के समय में परिवहन गतिविधियों में कमी के मद्देनजर तेल और पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट के कारण प्लास्टिक रीसाइक्लिंग में कमी ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को एक बड़ी चुनौती बना दिया है । जब तक कि प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं किया जाता है एसयूपी सहित विभिन्न पीपीई और पैकेजिंग सामग्री की खपत दुनिया भर में एक प्लास्टिक महामारी पैदा करने की दहलीज पर है। प्लास्टिक कचरे के कुप्रबंधन और कूड़ेदान से न केवल वायरस संचरण का खतरा हो सकता है, बल्कि स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण भी पैदा हो सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान प्लास्टिक कचरे के कुप्रबंधन के कारण बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्टों और समाचार पत्रों के आधार पर प्लास्टिक को एक दुष्ट प्रदूषक के रूप में मानने से समाज की सामान्य धारणा का निर्माण किया है। इस सामान्य दृष्टिकोण के विपरीत, कुप्रबंधन और संसाधनों के कम उपयोग उपभोक्ताओं का गैर-जिम्मेदार और लापरवाह रवैया प्लास्टिक प्रदूषण में योगदान देने और उसे बढ़ाने वाले प्रमुख उत्प्रेरक हैं। विशेष रूप से पीपीई और अन्य प्लास्टिक-आधारित चिकित्सा उपकरण महामारी के समय में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए एक जीवन रक्षक के रूप में उभरे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान प्लास्टिक के सभी पेशेवरों और विपक्षों, उनके प्रबंधन या कुप्रबंधन और पर्यावरण की तुलना करने के लिए एक समान मूल्यांकन की आवश्यकता है।

वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन और उपयोग पर महामारी के प्रभाव

कोरोन वायरस के संचरण की मानव-से-मानव को वायरल संक्रमण से बचाने के लिए फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा आम नागरिकों द्वारा प्लास्टिक-आधारित पीपीई के अनिवार्य उपयोग की आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी के कारण आवश्यक पीपीई किटों की मांग आसमान छू गई है, जिसने दुनिया भर में प्लास्टिक निर्माण और वितरण में जबरदस्त वृद्धि दिखाई है। वर्तमान महामारी में वायरल संक्रमण से निपटने के लिए, डब्लूएचओ ने एक हिस्से के रूप में 89 मिलियन फेशियल मास्क, 76 मिलियन दस्ताने, 30 मिलियन गाउन और 1.6 मिलियन गॉगल्स के साथ-साथ 2.9 मिलियन हैंड सैनिटाइज़र की मासिक मांग का अनुमान लगाया है। इसके अलावा, डब्ल्यूएचओ ने महामारी के दौरान दुनिया भर में विभिन्न चिकित्सा सुरक्षा उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में 40इ की मासिक वृद्धि का अनुमान लगाया था । इसी तरह, पीपीई के उत्पादन के लिए सीएजीआर को 2020 से 2025 तक लगभग 20इ स्पाइक दिखाने का अनुमान था । दुनिया भर में 7.8 बिलियन आबादी के लिए, फेशियल मास्क और मेडिकल ग्लव्स की मासिक खपत लगभग 129 बिलियन और 65 बिलियन बताई गई । वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, यूके में अपेक्षाकृत कम पुष्टि वाले ण्ध्छ्ऊ-19 मामलों वाले क्षेत्रों में भी मेडिकल किट का दैनिक उपयोग चौंका देने वाला स्तर तक पहुंच गया।

प्लास्टिक के उपयोग पर टेकअवे और ई-कॉमर्स खरीदारी का प्रभाव

दुनिया भर के कई देशों में महामारी के समय लगाए गए कुल लॉकडाउन ने लोगों को खाद्य पदार्थों और किराने के सामान सहित आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए ऑनलाइन खरीदारी और टेकअवे सेवाओं पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया है। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए ई-कॉमर्स खरीदारी और टेकअवे सेवाओं पर निर्भरता के परिणामस्वरूप पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए एसयूपी कैरी बैग और अन्य प्रकार के प्लास्टिक की मांग में वृद्धि हुई है। महामारी ने उपभोक्ता मांग और व्यवहार में बदलाव जैसे घबराहट की खरीदारी, खाद्य पदार्थों और किराने के सामान को जनता के बीच में लाने के लिए प्रेरित किया है और इसके परिणामस्वरूप कई देशों में प्लास्टिक आधारित पैकेजिंग वस्तुओं में वृद्धि हुई है। स्वच्छता संबंधी चिंताओं, घबराहट की खरीदारी और भंडारण के कारण उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव के कारण प्लास्टिक की आवश्यकता में काफी वृद्धि हुई है।

लॉकडाउन से गिरी कीमतें बढा उत्पादन

महामारी से प्रेरित लॉकडाउन के समय में परिवहन गतिविधियों में कमी के कारण तेल और पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट के कारण प्लास्टिक निर्माण की लागत में भारी कमी प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति के अनुपात में अचानक वृद्धि में योगदान देने वाला एक अन्य कारक है। इसने विनिर्माण उद्योगों को प्लास्टिक पुनर्चक्रण और प्लास्टिक उत्पादन के बीच चयन करने के लिए प्रेरित किया है। वर्तमान स्थिति में पूर्व की तुलना में आर्थिक रूप से व्यवहार विकल्प के रूप में उभरा है। महामारी के समय में एसयूपी के बढ़ते उपयोग ने प्लास्टिक उत्पादन में काफी वृद्धि की है। एक अधिक गंभीर खतरा दुनिया भर में स्पष्ट हो गया है कि विकासशील देश COVID-19 महामारी से पहले ही अपने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। एसयूपी पर प्रतिबंध हटाने या स्थगित करने और पीपीई के अभूतपूर्व उपयोग ने महामारी के दौरान प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में वृद्धि के बीच प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में कठिन चुनौतियों का सामना किया है।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

प्लास्टिक अपशिष्ट उपचार और निपटान की चुनौतियाँ

महामारी के दौरान प्लास्टिक उत्पादन पर एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक

महामारी से जो अधिक चिंताजनक मुद्दा उभरा है, वह एसयूपी के उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए एक लंबी लड़ाई की गति को उलट रहा है। प्लास्टिक निर्माताओं द्वारा प्रचारित और समर्थित प्लास्टिक बैग और कंटेनरों का पुनः उपयोग करके संक्रमण की चिंताओं के बीच, अमेरिका, यूके, कनाडा, पुर्तगाल जैसे कई देशों ने कोविड के समय में एसयूपी प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से रद्द या स्थगित कर दिया है। इस साल की शुरुआत में, अमेरिका स्ट्रॉ, टेकआउट कंटेनरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा था, और एसयूपी के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के प्रयास के रूप में नागरिकों को अपने रियूज बैग ले जाने के लिए अनिवार्य कर रहा था। लेकिन नोवेल कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण, पुनः प्रयोज्य बैग और अन्य कटलरी से चिपके हुए कोरोनावायरस के बारे में चिंताओं के बीच इस तरह के आंदोलनों को रोक दिया गया है। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रस्तावित राज्य-व्यापी प्रतिबंध मई 2020 तक रोक दिया गया है। हाल ही में, कैलिफोर्निया और ओरेगन जैसे राज्यों ने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध को निलंबित कर दिया है। थाईलैंड में प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने के लिए शुरुआत में डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद, देश अब अपने एसयूपी उत्पादन में 30% की वृद्धि देख रहा है।

महामारी के दौरान प्लास्टिक कचरा उत्पादन

महामारी ने अपशिष्ट उत्पादन और संरचना की गतिशीलता में बदलाव लाया है और इस तरह स्थानीय अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं और नियामक एजेंसियों के लिए एक कड़ी चुनौती पेश की है। फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों द्वारा ज्यादातर प्लास्टिक-आधारित पीपीई के अभूतपूर्व उपयोग के परिणामस्वरूप विश्व स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, स्वच्छता संबंधी चिंताओं के लिए एकल उपयोग के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (RT-PCR) को नियोजित करने वाले कोरोनावायरस परीक्षण किट के कई प्लास्टिक-आधारित भागों के निपटान ने प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को जन्म दिया है। इसके अलावा, महामारी के बीच ई-कॉमर्स खरीदारी और टेकअवे सेवाओं के लिए एसयूपी और प्लास्टिक-आधारित पैकेजिंग सामग्री के बढ़ते उपयोग ने प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को और बढ़ा दिया है । महामारी के समय में चिकित्सा उत्पादों और पैकेजिंग की बढ़ती वैश्विक मांग के कारण प्लास्टिक पैकेजिंग कचरा तेजी से उत्पन्न हो रहा है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वैश्विक प्रथाएं

पूर्व महामारी की स्थिति में अपशिष्ट उत्पादन को देखते हुए विश्व स्तर पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहले से ही अपर्याप्त है। अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे को आम तौर पर सामान्य परिस्थितियों में मध्यम परिवर्तन के साथ औसत अपशिष्ट प्रवाह और संरचना के साथ स्थिर-राज्य संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। महामारी के दौरान ज्यादातर प्लास्टिक कचरे वाले प्लास्टिक कचरे और बायोमेडिकल कचरे का कुशल प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न घटकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। कुछ एशियाई देश कचरे से निपटने के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं। जिससे सामान्य समुदाय के भीतर संक्रामक कोविड-19 उत्पन्न प्लास्टिक कचरे का ढेर लगा है। उदाहरण के लिए, कंबोडिया, फिलीपींस, थाईलैंड, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम और फिलिस्तीन जैसे विकासशील देशों को अपने संक्रामक बीएमडब्ल्यू को खुले लैंडफिल में डंप करने की सूचना मिली है। यह एक और उदाहरण है जहां संक्रमित पीपीई और चिकित्सा अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन से वातावरण में वायरल संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ सकती है।

(पृष्ठ 4 का शेष)

उपचार और निपटान के दृष्टिकोण से, मैकेनिकल रीसाइक्लिंग, भस्मीकरण और लैंडफिलिंग दुनिया भर में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे व्यापक रूप से नियोजित तरीके हैं। अपशिष्ट उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए, दुनिया भर में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग में महामारी के समय में तेज गिरावट देखी गई है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में कई राज्य महामारी के दौरान स्थानीय स्तर पर धन की कमी के कारण कुल 9000 ऐसी सुविधाओं में से नगरपालिका द्वारा संचालित रीसाइक्लिंग कार्यक्रमों को या तो निलंबित या कम कर रहे हैं। गंभीर धन संकट के कारण विकासशील देशों में ब्राजील, ग्वाटेमाला, हैती, भारत, इंडोनेशिया, केन्या जैसे देशों में रीसाइक्लिंग कार्यक्रम में व्यवधान और भी बढ़ गया है।

विकासशील दुनिया में प्रचलित अनौपचारिक पुनर्चक्रण क्षेत्र, खराब संग्रह और पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक के लिए बाजार की मांग में कमी के कारण महामारी का खामियाजा भुगत रहा है। कई प्लास्टिक रीसाइक्लिंग तकनीकें अकार्बनिक, एडिटिव्स, गंदगी और पॉलीमर क्रॉस-संदूषण के रूप में अशुद्धियों के लिए अतिसंवेदनशील होती हैं। प्लास्टिक कचरे का भस्मीकरण, अलगाव और अशुद्धियों की परवाह किए बिना, अपशिष्ट गर्मी वसूली के प्रावधान के साथ सुरक्षित विनाश के लिए 800-1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज में संदूषण की कम संभावना के साथ इसकी कम श्रम शर्त को देखते हुए एक उचित विकल्प हो सकता है । कचरे की मात्रा के आधार पर, भस्मीकरण अपशिष्ट उत्पादन्न 10 टीपीडी के लिए एक आदर्श विकल्प है, जबकि ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेव विकिरण जैसी अन्य थर्मल तकनीकों को ष10 टीपीडी के अपशिष्ट उत्पादन के लिए पसंद किया जाता है। हालांकि, महामारी के दौरान बड़ी चुनौती प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि के साथ मौजूदा भस्मीकरण क्षमता को व्यापक अंतर से भंग करना है।

कचरा प्रबंधन सूची में सबसे कम पसंदीदा विकल्प होने के बावजूद, मुख्य रूप से विकासशील देशों में प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए लैंडफिलिंग आमतौर पर पसंदीदा तरीका है। हालांकि, सैनिटरी लैंडफिलिंग सुविधाओं से लैस कुछ मेगा शहरों को छोड़कर विकासशील दुनिया के कई हिस्सों में अवैज्ञानिक लैंडफिलिंग और कचरे का अंधाधुंध डंपिंग प्रचलित है। इसके परिणामस्वरूप लैंडफिल और डंपसाइट्स की क्षमता समाप्त हो सकती है, गंभीर स्थान की कमी, रिसाव, और प्लास्टिक कचरे का कुप्रबंधन, जहरीले रसायनों का रिसाव आदि हो सकता है । लैंडफिलिंग को प्राथमिकता देने से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरे को कूड़ा-करकट और खुले में जलाया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय पदचिह्न में वृद्धि हो सकती है।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए संभावित तकनीकी समाधान

महामारी काल सीमित उपलब्ध विकल्पों और मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे की प्रभावकारिता पर भारी बोझ के साथ, प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह, अलगाव, और पीपीई किट के परिशोधन सहित बाद के उपचार के लिए नए दृष्टिकोण और तकनीकी समाधानों का एकीकरण, के दौरान और बाद में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने में फायदेमंद हो सकता है । मौजूदा कचरा प्रबंधन प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के अलावा, यह उम्मीद की जाती है कि प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि से निपटने के लिए नए दृष्टिकोण और तकनीकी समाधान आकस्मिक हो सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देश 900-1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज में पीपीई और प्लास्टिक कचरे सहित अन्य संक्रामक कचरे को अनिवार्य रूप से जलाने का सुझाव देते हैं।

हालांकि, प्लास्टिक कचरे के उत्पादन और संरचना की गतिशीलता में महामारी से प्रेरित उछाल से निपटने के लिए भस्मक की डिजाइन क्षमता को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। इसके अलावा, द्वितीयक प्रदूषण को कम करने के लिए भस्मक को उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के साथ संवर्धित करने की आवश्यकता है। उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण तंत्र के साथ संवर्धित भस्मीकरण तकनीक यूरोप में सबसे अधिक प्रचलित है, डेनमार्क, फिनलैंड, पोलैंड और स्वीडन जैसे देशों में बाजार की ऊर्जा की मांग को पूरा करने वाले 50इ से अधिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक कचरे को भस्म करना जारी है। स्पेन में, सीमेंट संयंत्रों को आवश्यकता पड़ने पर कचरे को सह-भस्म करने की अनुमति है। कड़े वायु प्रदूषण नियंत्रण के साथ एकीकृत भस्मीकरण महामारी के समय में प्लास्टिक कचरे और बीएमडब्ल्यू की बढ़ती पीढ़ी से निपटने के लिए एक अल्पकालिक, सुविधाजनक विकल्प हो सकता है। हालांकि, दीर्घकालिक समाधान अपशिष्ट प्रबंधन पदानुक्रम के बाद रीसाइक्लिंग प्रतिमान को अपनाने में निहित है।

वर्तमान संकट के दौरान अत्यधिक मांग के जवाब में सुरक्षात्मक चिकित्सा किटों की कमी ने दुनिया भर के कई क्षेत्रों में पीपीई की आपूर्ति श्रृंखला को महत्वपूर्ण रूप से चुनौती दी है। वैश्विक मांग में वृद्धि को देखते हुए पीपीई की आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए अभिनव तकनीकी समाधान और उन्नत कीटाणुशोधन प्रथाएं समय की आवश्यकता हैं। उपयोग किए गए पीपीई, एफएफआर, सर्जिकल और प्रक्रिया मास्क के परिशोधन को प्लास्टिक-आधारित चिकित्सा सुरक्षा गियर की कमी को कम करने के लिए एक संभावित अस्थायी समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो उनके पुनः उपयोग के कारण फ़िल्टरिंग और फिट परीक्षण दक्षता पर बड़ा प्रभाव डाले बिना संतोषजनक सुरक्षा प्रदर्शन प्रदान करता है। कोविड-19 से उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की मात्रा और प्रकार, परिवहन, परिचालन रखरखाव, और लागत अर्थशास्त्र जैसे प्रभावशाली कारकों के आधार पर विभिन्न परिशोधन विधियों का चयन कहीं और उल्लिखित किया गया है।

कुशल योजना और महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेपों की कमी ने पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के रिसाव और कुप्रबंधन को बढ़ा दिया, जिससे प्रचलित महामारी के दौरान एक और खतरा पैदा हो गया। हालांकि ण्ध्ब्ब्ऊ-19 के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की मात्रा के प्रारंभिक आंकड़े चौंका देने वाले हैं, लेकिन यह समझने में समय लगेगा कि इस तरह के अतिरिक्त प्लास्टिक कचरे का पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा। हालाँकि, COVID-19 से उत्पन्न प्लास्टिक कचरे के नतीजों का उपयोग एक मील का पत्थर के रूप में किया जा सकता है जिसे आपातकालीन उपायों और दीर्घकालिक अपशिष्ट प्रबंधन विकल्पों के साथ तैयार किया जा सकता है जिससे हमें बेहतर और सुरक्षित भविष्य बनाने में मदद मिलती है। महामारी के दौरान बढ़ते अपशिष्ट उत्पादन के बीच प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से संबंधित मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत नीतियां और टिकाऊ दृष्टिकोण और पहल आज समय की जरूरत है। महामारी के दौरान उत्पन्न स्थिरता चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया भर में कॉर्पोरेट क्षेत्रों, वैज्ञानिक समुदाय और सरकारों से स्थायी दृष्टिकोण के साथ तकनीकी पहलुओं में प्रगति की आवश्यकता है। दुनिया भर में नियामक एजेंसियों द्वारा समर्थित उत्तरदायी पुनर्प्राप्ति योजनाओं और रणनीतियों को महामारी के कई विस्तार और वैश्विक गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय तनावों को प्रभावित करने वाली गहरी जड़ों पर विचार करना चाहिए। कोविड-19 संकट से उत्पन्न प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए आज किए गए स्थिरता उपाय प्रदूषण मुक्त समाज की दिशा में बहुप्रतीक्षित परिवर्तनकारी परिवर्तनों को अमल में लाने के अवसर के रूप में कार्य करते हैं। कुछ दृष्टिकोणों या समाधानों के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अन्य छोटी, मध्यम या लंबी अवधि में ध्यान देने वाली मुख्य चुनौतियों को वर्गीकृत करके लंबे समय तक महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी।

■ कोविड-19 से उत्पन्न प्लास्टिक कचरे को संरचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ संभालना आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, सरकार, हितधारकों और नीति निर्माताओं को कुशल अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थिरता को पहचानना चाहिए। रोकथाम, अलगाव और उपयुक्त प्लास्टिक अपशिष्ट उपचार को सुनिश्चित करने के लिए सभी चरणों में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल से गुजरना चाहिए ताकि इस महामारी से प्रकृति को सामना करने में मदद मिल सके।

■स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सलाह और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, किसी भी कूड़े और कुप्रबंधन से बचने के लिए इस्तेमाल किए गए पीपीई को इकट्ठा करने और निपटाने के लिए अलग-अलग परिवारों द्वारा रंग-कोडित बैग का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे इस्तेमाल किए गए पीपीई के उचित संग्रह और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक स्तर पर रंग-कोडित डिब्बे तैनात किए जाने चाहिए। इसके अलावा, साइट पर संक्रामक प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए मोबाइल उपचार सुविधाओं की तैनाती पर विचार किया जाना चाहिए।

■ बेहतर पुनर्चक्रण के लिए मिश्रित या मल्टी लेयर मटेरियल के बजाय समान संरचना वाली प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत नीतियां तैयार की जानी चाहिए।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

प्लास्टिक अपशिष्ट उपचार और निपटान की चुनौतियाँ

(पृष्ठ 5 का शेष)

प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री को एसयूपी के पुनर्चक्रण को बढ़ाने के लिए राल कोडित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, चक्रीयता सुनिश्चित करने के लिए मिश्रित प्लास्टिक कचरे को ईंधन और रसायनों जैसे मूल्यवान उत्पादों में प्रबंधित करने के लिए रासायनिक पुनर्चक्रण जैसी स्थायी तकनीकों को विकसित करने के लिए अनुसंधान प्रयासों की आवश्यकता है।

■ हेल्थकेयर केंद्रों और वैज्ञानिक संस्थानों को कार्यात्मक दक्षता से समझौता किए बिना पीपीई, विशेष रूप से एफएफआर को पुनः संसाधित और पुनः उपयोग करने के लिए विभिन्न परिशोधन विधियों पर विचार करना चाहिए। एथिलीन ऑक्साइड और वीएचपी जैसे व्यावसायिक रूप से उपलब्ध रसायनों के साथ यूवी विकिरण, शुष्क और नम गर्मी उपचार का उपयोग एफएफआर के प्रभावी परिशोधन के लिए वैकल्पिक समाधान के रूप में किया जा सकता है। इस तरह के परिशोधन के तरीके प्लास्टिक-आधारित सुरक्षा किटों की आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करेंगे और प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को कम करेंगे, जिससे कम करने और पुनः उपयोग जैसे स्थायी दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

■महामारी के बीच पीपीई की मांग को पूरा करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल और पुनः प्रयोज्य पीपीई किट विकसित करने में अनुसंधान और उत्पाद नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विनिर्माण उद्योगों को बायो-प्लास्टिक या कम्पोस्टेबल प्लास्टिक सामग्री जैसे बायो-प्लास्टिक और बायोमास से बने कम्पोस्टेबल बैग के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें उच्च गिरावट और पुनर्चक्रण क्षमता हो। इसके अलावा, ऐसे जैव-प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए उपयुक्त संबद्ध बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए।

■प्लास्टिक कचरे के विकास को कम करने के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्लास्टिक-आधारित फेसमास्क के बजाय पुनः प्रयोज्य कपड़े के फेसमास्क के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यदि कपड़े पर आधारित या इसी तरह के कपड़े

से बने मास्क समान स्तर की सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो महामारी के बीच प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए पुनः प्रयोज्य फेस कवरिंग का विकल्प चुनने के लिए पहल की जानी चाहिए।

■हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों में सकारात्मक जीवनशैली में बदलाव महामारी के दौरान और बाद में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए एक संभावित चालक के रूप में कार्य कर सकता है। ऑनलाइन खरीदारी और ऑर्डर कैसे करें, इस पर हमारे विकल्पों पर पुनर्विचार करने से इष्टतम संसाधन खपत हो सकती है। उदाहरण के लिए, रेस्तरां से पैक किए गए भोजन से परहेज करना और स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों पर अधिक जोर देना, उचित कीटाणुशोधन के साथ पुनः प्रयोज्य शॉपिंग बैग का उपयोग करना, साबुन डिस्पेंसर बोतल या रिफिल करने योग्य हैंड वॉश / हैंड सैनिटाइज़र का चयन करना कुछ पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार हैं जो हम कर सकते हैं प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपने पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयास में अपनाएं।

■ इस महामारी से उभरने वाले अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को लचीला बनने के लिए रचनात्मकता की आवश्यकता है। नई तकनीक और आउट-ऑफ-बॉक्स सोच को अपनाकर कचरा प्रबंधन में नवीनता और रचनात्मकता नया सामान्य होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) की तैनाती के साथ काम के माहौल, स्वचालन और रोबोटिक्स में सामाजिक गड़बड़ी और कर्मचारियों की सुरक्षा के कारण प्रतिबंधित शारीरिक सहयोग प्लास्टिक कचरे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाल ही में, कई अपशिष्ट प्रबंधन उद्यमों को ण्ध्ब्ब्ऊ-19 के दौरान और उसके बाद उत्पन्न कचरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ि) पर काम करने की सूचना मिली है। इसके अलावा, कई उन्नत तकनीकों जैसे थर्मल इमेजिंग, हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग, लेजर-प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी (एलआईबीएस) पर शोध किया जा रहा है ताकि रीसाइक्लिंग के लिए मिश्रित कचरे से प्लास्टिक के स्वचालित वर्गीकरण और पृथक्करण पर शोध किया जा सके।

■पायरोलिसिस, गैसीकरण, हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन और अन्य थर्मल रूपांतरण तकनीकों जैसी स्वचालित अपशिष्ट उपचार तकनीकों को प्लास्टिक के अधिक अनुपात में ऊर्जा और मूल्यवान उप-उत्पादों के साथ कोविड-19 को बदलने के लिए नियोजित किया जा सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ऐसी तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा को अधिकतम किया जा सके।

■सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान शुरू किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को उचित प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान की जिम्मेदारी लेने के साथ-साथ अंधाधुंध उपयोग द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय परिणामों को समझने के लिए शिक्षित करके जन जागरूकता पैदा की जा सके। इसके अलावा, प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे के पर्यावरणीय प्रभाव को अगली पीढ़ी के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

कोविड- 19 संकट ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक रक्षक के रूप में प्लास्टिक की अनिवार्यता और इसके आंतरिक गुणों के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर प्रकाश डाला है। प्लास्टिक के उपयोग और अपशिष्ट उत्पादन में महामारी से प्रेरित वृद्धि को देखते हुए, इसके कुप्रबंधन और संसाधन मूल्य के कम उपयोग के कारण एक बुरे प्रदूषक के रूप में प्लास्टिक के बारे में सामान्य धारणा को और मजबूत किया गया है। प्लास्टिक की कार्यात्मकताओं और कमियों की तुलना करके एक न्यायसंगत मूल्यांकन से पता चलता है कि उपभोक्ताओं के रवैये और खराब सामाजिक जागरूकता के व्यवहार संबंधी पहलू और मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की अपर्याप्तता प्रमुख चालक के रूप में प्लास्टिक को पर्यावरण प्रदूषक बनाते हैं।

यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि यदि परिपत्र अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को ठीक से एकीकृत किया जाए तो प्लास्टिक प्रदूषक के बजाय एक रक्षक हो सकता है। सर्कुलर इकोनॉमी को प्राथमिकता देने के लिए, आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखने के लिए कुशल परिशोधन विधियों को अपनाकर पीपीई, विशेष रूप से एफएफआर के पुनः प्रसंस्करण और पुनः उपयोग में निरंतर प्रगति की जानी चाहिए। इसके अलावा, पर्यावरण के अनुकूल और पुनः प्रयोज्य पीपीई किट और उच्च पुनर्चक्रण के साथ जैव-प्लास्टिक से बने कैरी बैग विकसित करने में अनुसंधान और उत्पाद नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्लास्टिक अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण के लिए एआई, एमएल और आईओटी की तैनाती के साथ मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और बुनियादी ढांचे को स्वचालित किया जाना चाहिए। संक्रामक प्लास्टिक कचरे की नसबंदी के बाद यांत्रिक पुनर्चक्रण को नीति निर्माण के साथ प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि परिपत्र अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जा सके।

मिश्रित प्लास्टिक कचरे को ईंधन और रसायनों जैसे मूल्यवान उत्पादों में प्रबंधित करने के लिए रासायनिक पुनर्चक्रण निश्चित रूप से परिपत्र प्राप्त करने में मदद करेगा। प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए उपभोक्ताओं के व्यवहारिक रवैये और सामाजिक जागरूकता में सुधार के लिए आईईसी अभियान और शैक्षिक पाठ्यक्रम की दीर्घकालिक योजना के रूप में आवश्यकता है। जागरूकता सृजन के लिए उपभोक्ताओं की शिक्षा के साथ-साथ सर्कुलर इकोनॉमी प्रतिमान की ओर संक्रमण के लिए मजबूत नीतियों द्वारा समर्थित सुरक्षित प्रथाओं और टिकाऊ तकनीकी समाधान प्लास्टिक को उच्च कार्यक्षमता वाले संरक्षक से प्रदूषक बनने के लिए प्रतिबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

'माँ सरस्वती वंदना'

काव्य अमृत के रस में डूबी लेखनी
मेरे तन पे हे मईया छिड़क दीजिए
सूखे पत्तों से मेरी है शब्दावली
नव सृजन जल से आकर भिगो दीजिये
मै अज्ञानी अभी हूं बालक माँ सुनो
मेरे तम को करुणा से हर लीजिए
चाटुकारी नेताओं की कर ना सकूँ
सद विचारों से माँ मुझको भर दीजिए
डगमगाए कभी न मेरी लेखनी
वाणी मे आकर के मुखर कीजिये
काव्य अमृत....

माँ महादेव से मेरी विनती कीजिए
हम कोरोना से तिल तिल के हैं मर रहे
अब ये वैक्सीन मास्क निरर्थक हुआ
हे भोलेनाथ चमत्कार कर दीजिए
मेरी कृति मे मानव जाति का हो भला
संस्कारों से माँ मुझको भर दीजिए
काव्य अमृत....

राष्ट्र प्रति जो समर्पित मेरा काव्य हो
राष्ट्र सेवा से सिंचित बहर दीजिए
मेरी शब्दों से कम्पित हो चीन और पाक़
मेरी कविता को विस्फोटक ही कर दीजिए
जा गिरे वो कराची, शंघाई, लाहौर
छंदों को बम परमाणु कर दीजिए
काव्य अमृत...

मै गद्दारों की छाती मे बैठा रहूं
मेरी कृति को हथौड़ा सा बल दीजिये
मेरी कविता से प्रेरित हो जाएँ युवा
कृति मे उनकी समस्या का हल दीजिए
लिखते लिखते वतन पर अगर मर मिटूं
अपने आँचल का मईया कफ़न दीजिए
काव्य अमृत....

मै विकारों मे अब तक समाहित रहा
निज चरण जल से हे माँ नहला दीजिए
ना कोई लोभ है धन सम्पदा का मुझे
जब भी जन्मूँ ये भारत वतन दीजिए
मेरे जाने के बाद गुनगुनाएँ सभी
मेरे गीतों को अमरता का वर दीजिए
काव्य अमृत....

नाम- सुजीत जायसवाल 'जीत'
जिला -कौशाम्बी
प्रयागराज
उत्तरप्रदेश
सम्पर्क :8858566226, 7007560002

व्यापारी प्रकोष्ठ ने बुजुर्गों को पहुंचाया वृद्धाश्रम

मानवता की मिसाल इंदौर में फिर से देखने को मिली

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के महानगर मीडिया प्रभारी संतोष वाधवानी के (रत्न विशेषज्ञ) ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा नगर अध्यक्ष निर्मल वर्मा घुंगरू के निर्देश पर बेसहारा बुजुर्ग को प्रशासन द्वारा आसरा दिलवाया गया है। इन्दौर के निपानिया क्षेत्र से रहवासी योगेंद्र चौधरी, शरद संघी , जय्यू जोशी ओर सुनील ठाकुर , एवं सन्तु सेना को जानकारी दी गई कि एक वृद्ध अमर सिंह जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष के आसपास सिक्का कॉलेज के बाहर यह वृद्ध परेशान होते इधर उधर भटक रहा था। सुनील ठाकुर और जय्यू जोशी द्वारा वृद्ध से पूछताछ में बताया कि उसके बेटे ने जमीन बेच दी और उसे घर से बहन के वह जाने का बोल कर किसी गाड़ी में बैठा दिया।और विगत 7 दिनों से बायपास के आसपास घूम रहे है।बेटा पीथमपुर में किसी कंपनी में कार्य करता है। पास के रहवासियों द्वारा नास्ता दिया जिसे खाकर वही बैठगये ओर कहि जा भी नही रहै थे।सभी मित्रो की मदद से 1 वैन में बैठाया।ओर सबसे पहले कोविड का रैपिड टेस्ट करवाया जिससे रिपोर्ट नेगेटिव आई।अब इन्दोर की सभी वृद्धाश्रम में बात की पर किसी ने भी उन्हें रखने से मना कर दिया। फिर जय्यू जोशी ने भाजपा व्यापारी प्रकोष्ट इंदोर के अध्यक्ष निर्मल वर्मा घुँघरू जी जोकि एक संस्था विजय भी चलाते है उनसे संपर्क किया उन्होंने इन्दोर के अपर कलेक्टर श्री अभय बेडेकर जी से तुरंत सम्पर्क कर एक्शन लिया और वृद्ध बुजुर्ग को तुरंत जीवन ज्योति आश्रम में निवास की व्यवस्था करवा दी। ओर उन्हें सही जगह पहुचने में मदद की,ओर उन्होंने इस बुजुर्ग को उनका हक दिलाने के लिए भी पुलिस प्रशासन से मदद का अनुरोध किया। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ और युवा समाजसेवियों की सक्रियता से एक बुजुर्गों को आसरा मिल गया।

रिलायंस जियो समुद्री दूरसंचार-केबल नेटवर्क बिछाने की वैश्विक मुहिम में शामिल

नयी दिल्ली। एजेंसी

रिलायंस इंस्ट्रीज की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो भारत और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट (डेटा) की जरूरतों को पूरा करने के लिये अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल प्रणाली बिछाने में जुटी है। कंपनी ने इसके लिये विश्व की कई प्रमुख वैश्विक साझेदारों और विश्व स्तरीय सबमरीन केबल आपूर्ति सबकॉम के साथ हाथ मिलाया है। देश की प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी रिलायंस जियो ने सोमवार को एक बयान में कहा कि फिलहाल उसकी अगली पीढ़ी की दो सबमरीन केबल डालने की योजना है। इसमें एक प्रणाली भारत को सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया तथा दूसरी इटली और पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों के रास्ते एशिया प्रशांत बाजारों से जोड़ेगी। बयान के अनुसार, ''रिलायंस जियो भारत और आसपास के क्षेत्रों के डेटा जरूरतों को पूरा करने के लिये अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल प्रणाली तैयार कर रही है। क्षेत्र में डेटा की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए कंपनी फिलहाल अगली पीढ़ी की दो सबमरीन केबल डालेगी।'' इसमें कहा गया है, ''भारत-एशिया-एक्सप्रेस (आईएएक्स) प्रणाली भारत को पूर्व की ओर सिंगापुर और उससे आगे कनेक्ट करेगी जबकि भारत-यूरोप-एक्सप्रेस (आईईएक्स) प्रणाली भारत को पश्चिम की ओर पश्चिम एशिया और यूरोप से जोड़ेगी।'' आईएएक्स और आईईएक्स से भारत और भारत से बाहर डेटा और क्लाउड सेवाओं को पहुंचाने की क्षमता बढ़ेगी तथा ग्राहकों को और बेहतर सेवाएं मिलेगी।बयान के अनुसार इस उच्च गति की प्रणाली से 16,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक 200 टीबीपीएस (टेरा बिट प्रति सेकेंड) से अधिक की क्षमता प्रदान करेगा। रिलायंस जियो के अध्यक्ष मैथ्यू ओमन ने इस बारे में कहा, ''...रिलायंस जियो स्ट्रीमिंग वीडियो, रिमोट वर्कफोर्स, 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी तरह के पहले भारत-केंद्रित आईएएक्स और आईईएक्स सिस्टम बनाने का नेतृत्व कर रही है।'' उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के बीच इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम तक पहुंचाना एक चुनौती है किंतु इस महामारी ने डिजिटल सेवाओं के लिए उच्च-स्तरीय 'कनेक्टिविटी' की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है।

एडीबी ने रिकॉर्ड 3.92 अरब डॉलर के कर्ज मंजूर किए

नई दिल्ली। एजेंसी

एशियाई विकास बैंक ने कहा कि उसने भारत को 2020 में 13 परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड 3.92 अरब अमेरिकी डॉलर के कर्ज स्वीकृत किए, जिसमें कोविड-19 महामारी की रोकथाम तथा बचाव से संबंधित परियोजनाओं के लिए 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण शामिल हैं। मनीला स्थित बहुपक्षीय एजेंसी ने कहा कि उसने भारत में महामारी को रोकने और गरीब और अन्य कमजोर समूहों को राहत देने के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए आपातकालीन सहायता दी है। एडीबी ने शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी सरकार को सहायता दी। एडीबी ने कहा कि 1986 में उसके द्वारा ऋण देने की शुरुआत के बाद से भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक ऋण प्रतिबद्धता है। भारत में एडीबी के कंट्री डायरेक्टर ताकियो कोनिशि ने कहा, इसके आगे भी, एडीबी भारत को कोविड-19 संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए अतिरिक्त संसाधन देने को तैयार है, जिसमें देश के टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने और भविष्य के जोखिमों का मुकाबला करने के लिए सक्षम स्वास्थ्य प्रणाली की स्थापना, छोटे कारोबारियों की रक्षा के लिए सहायता और शिक्षा तथा सामाजिक संरक्षण शामिल है। एडीबी ने कहा कि उसने 2020 के दौरान भारत में ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन के लिए अपनी नियमित सहायता जारी रखी।

भारतीय अर्थव्यवस्था कब करेगी अच्छा प्रदर्शन, MPC मेंबर ने दिया यह जवाब

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सदस्य आशिमा गोयल ने मंगलवार को कहा कि एक बार महत्वपूर्ण संख्या में लोगों को टीका लगने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसकी वजह है कि मांग में बढ़ोतरी, वैश्विक सुधार और आसान वित्तीय स्थितियां आर्थिक कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देंगी। उन्होंने कहा कि भारत इस समय कोविड की दूसरी लहर के भयानक असर से जूझ रहा है, लेकिन लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था को हुआ नुकसान काफी कम है और इसके चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही से आगे बढ़ने की आशंका बहुत कम है। उन्होंने कहा, ''भारत में वैक्सीन उत्पादन का केंद्र बनने की क्षमता है और वह जल्द ही इस दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम होगा। एक बार जब टीकाकरण महत्वपूर्ण आबादी तक पहुंच जाएगा, तो अर्थव्यवस्था मांग, वैश्विक सुधार और आसान वित्तीय स्थितियों के चलते अच्छा प्रदर्शन करेगी।''

असर दिखा रहे हैं स्थानीय लॉकडाउन

प्रख्यात अर्थशास्त्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन और प्रतिबंधों के चलते संक्रमण में सफलतापूर्वक कमी आई है। उन्होंने कहा, ''यह आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए कम बाधाकारी है, क्योंकि यह स्थानीय जरूरतों के अनुसार है और इसके लिए पूरी तरह पूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है।'' उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत में राजकोषीय विस्तार सामान्य रहा है और मध्यम अवधि में इसमें बदलाव संभव होगा।

5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में लगेगा वक्त

उन्होंने कहा, ''चूंकि, भारत की दीर्घकालिक वृद्धि गाथा बरकरार है, इसलिए रेटिंग एजेंसियां देश को समय देने के लिए तैयार होंगी।'' साथ ही उन्होंने कहा कि गैर-कर वित्त पोषित खर्च में लगातार बढ़ोतरी समस्याएं पैदा कर सकती है। वर्ष 2024-25 तक भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सरकार के लक्ष्य पर गोयल ने कहा कि इतनी व्यापक और अप्रत्याशित महामारी के बाद इस लक्ष्य को हासिल करने में अधिक समय लगेगा। उन्होंने कहा कि साथ ही कोविड-19 से संबंधित अनिश्चितताएं अभी खत्म नहीं हुई हैं।

भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने 2021 की पहली तिमाही में 'अपेक्षाकृत बेहतर' प्रदर्शन किया: संरा

संयुक्त राष्ट्र। एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने इस साल की पहली तिमाही में आयात और निर्यात के लिहाज से अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ''अपेक्षाकृत बेहतर'' प्रदर्शन किया है। कोविड-19 संकट से उबरने के बाद इस दौरान वैश्विक व्यापार अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) ने अपनी ताजा वैश्विक व्यापार रिपोर्ट में बुधवार को कहा कि 2021 की पहली तिमाही में वस्तुओं और सेवाओं का वैश्विक व्यापार इससे पिछली तिमाही के मुकाबले चार प्रतिशत और एक साल पहले की समान तिमाही के मुकाबले लगभग 10 प्रतिशत बढ़ा। अंकटाड ने कहा कि 2021 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार संकट के पहले के मुकाबले अधिक था, और यह 2019 की पहली तिमाही के मुकाबले तीन प्रतिशत अधिक रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के मजबूत प्रदर्शन के चलते तेजी का ये रुझान बरकरार रहेगा। अंकटाड ने कहा, ''चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 2021 की पहली तिमाही में अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से चीन के निर्यात में मजबूत वृद्धि हुई है। इसके विपरीत रूस से निर्यात 2019 के औसत से काफी कम रहा।'' भारत के बारे में बताया गया कि 2020 की पहली तिमाही के मुकाबले 2021 की समान तिमाही में वस्तुओं का आयात 45 प्रतिशत और सेवाओं का आयात 14 प्रतिशत बढ़ा। समीक्षाधीन अवधि में भारत से वस्तुओं का निर्यात 26 प्रतिशत और सेवाओं का निर्यात दो प्रतिशत बढ़ा।

कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की आपूर्ति पर नजर रखे हुये है सरकार: मंडाविया

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने बुधवार को कहा कि सरकार कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न आवश्यक दवाओं की आपूर्ति पर नजर रखे हुये है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मंत्री ने कहा कि उत्पादन और आयात बढ़ने के साथ कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली सभी दवाइयां अब भारत में उपलब्ध हैं। मंडाविया ने कहा, 'आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, मांग का प्रबंधन और उचित दाम पर उपलब्धता के साथ तीन सूत्रीय रणनीति के साथ इन दवाइयों की उपलब्धता की निगरानी की जा रही है।' उन्होंने बताया कि सरकार रेमडेसिविर, इनोक्सापरिन, मिथाइलप्रेड्निसोलोन, डेक्सामेथासोन, टोसिलिजुमाब और इवरमेक्टिन जैसी विभिन्न 'प्रोटोकॉल दवाओं' की आपूर्ति पर नजर रखे हुए हैं। मंडाविया ने कहा कि इसके अलावा फैविपिराविर, एम्फोटेरिसिन और एपिक्सामैब जैसी दूसरी दवाइयों की आपूर्ति की भी निगरानी की जा रही है। मंत्री ने कहा कि रेमडेसिविर का उत्पादन करने वाले संयंत्रों की संख्या 20 से बढ़ाकर 60 कर दी गयी है जिसके साथ केवल 25 दिनों में इस दवा की उपलब्धता तीन गुना बढ़ गयी है। इसके उत्पादन में दस गुणा वृद्धि हुई है। अप्रैल में जहां 10 लाख शीशी प्रति माह बन रही थी वहीं मई 2021 में यह एक करोड़ तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि बाकी महत्वपूर्ण दवाओं का उत्पादन भी बढ़ाया गया है।

News यू कैन USE

भारतीय आईटी, कारोबार सेवाओं के बाजार में 5.41 प्रतिशत की वृद्धि : आईडीसी

नयी दिल्ली। एजेंसी

संगठनों पर कोविड-19 से पड़े असर की वजह से देश का आईटी और व्यावसायिक सेवाओं के बाजार में 2020 में वृद्धि 5.41 प्रतिशत की अपेक्षा कृत धीमी रही। वर्ष के दौरान यह बाजार 13.41 अरब डॉलर का रहा। अनुसंधान कंपनी आईडीसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हालांकि आईटी और व्यावसायिक सेवाओं के बाजार का आंकड़ा 2020-2025 के बीच वार्षिक 7.18 की चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ बढ़ने और क्लाउड एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे क्षेत्रों में बढ़ते व्यय के सहारे 2025 के अंत तक करीब 19 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। आईडीसी के मुताबिक इस बाजार में 2019 में 8.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी लेकिन 2020 में कोविड-19 से असर से वृद्धि दर में गिरावट आयी। बीते साल (2020) आईटी और व्यापार सेवाओं के बाजाकर में आईटी सेवा वर्ग का योगदान 77.06 प्रतिशत था और इसमें 5.97 की वृद्धि हुई जो 2019 में 8.91 प्रतिशत थी। आईडीसी इंडिया के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक (आईटी सेवाएं) हरीश कृष्णकुमार ने कहा कि सभी क्षेत्रों के उद्यमों ने डिजिटल बदलाव में निवेश करना शुरू कर दिया है क्योंकि महामारी से यह बात साफ हो गयी है कि डिजिटल तौर-तरीके को बेहतर रूप से अपनाने वाले कारोबार पारंपरिक आईटी प्रणालियों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

ट्रक आपरेटरों की सामान, सड़क, यात्री करों से दो तिमाही तक छूट दिये जाने की मांग

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

ट्रक परिचालकों की संस्था एआईएमटीसी ने मंगलवार को सड़क कर के साथ साथ माल और यात्री करों से भी कम से कम दो तिमाहियों तक छूट दिये जाने की मांग की है। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्ट आपरेटर इस समय भारी वित्तीय तंगी से गुजर रहे हैं और उनके 65 से 70 प्रतिशत ट्रक खाली खड़े हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में 'आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के अध्यक्ष कुलतरन सिंह अटवाल ने राज्यों में वैधानिक दस्तावेजों के नवीनीकरण में होने वाली देरी पर जुर्माने से 30 सितंबर तक छूट देने की भी मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि माल ढुलाई करने वाले हों या फिर यात्री वाहन चलाने वाले ट्रांसपोर्टर, छोटे अथवा बड़े, इस समय सभी भारी वित्तीय तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। उनके 65 से 70 प्रतिशत वाहन बिना काम के खड़े हैं। एआईएमटीसी ने कहा, ''वर्तमान में व्यापार की कठिन स्थिति को देखते हुये .... ट्रांसपोर्टरों के लिये मोटर वाहन कर, सड़क कर, यात्री कर का भुगतान करना भी मुश्किल हो रहा है। इस कर का भुगतान एक अप्रैल 2021 से लंबित है।'' देश में रोजाना कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाल के सप्ताह में यह संख्या तीन लाख के पार जा चुकी है। इसकी वजह से कई राज्यों को लोगों और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी है। लॉकडाउन की वजह से उद्योग एवं व्यापार प्रभावित हुआ है और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र पर भी इसका असर पड़ना लाजिमी है।

कोरोना संकट से पस्त भारत की जीडीपी पर शॉपिंग कार्ट का क्या असर पड़ सकता है?

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत में कोरोना संकट के दूसरे चरण का अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत में कोरोना के बढ़ते संकट की वजह से ग्राहक अब खर्च करने की जगह बचत करने पर ध्यान देने लगे हैं। पिछले साल की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में आई कमजोरी की वजह आपूर्ति संबंधी दिक्कतें थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक रिसर्च रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। कोरोना के बढ़ते संकट की वजह से मौजूदा तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट पर ब्रेक लग सकता है। इसकी मुख्य वजह ग्राहकों की मांग में आई बड़ी कमजोरी रह सकती है। कोरोना संक्रमण के दौर में बहुत से लोग अब अपने खर्च को टालने लगे हैं। इस वजह से भारत की जीडीपी (उअ्ङ) काफी प्रभावित हो सकती है। क्वांट इको रिसर्च की इकनॉमिस्ट युविका सिंघल ने भारत के चालू वित्त वर्ष के जीडीपी ग्रोथ (उअ्ङ उैदूै) अनुमान में 150 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है और अब इसे 10 फ़ीसदी कर दिया है। सिंघल ने कहा, 'ग्राहकों की मांग और खपत में पिछले साल की तुलना में अधिक असर देखने को मिल सकता है। अब तक भारत की अर्थव्यवस्था वी शेप रिकवरी के मूड में थी, लेकिन खपत घटने की वजह से इस साल भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ यू शेप की रह सकती है।

गांव तक पहुंचा कोरोना

भारत में आमतौर पर बचत करने वाले ग्राहक अब जोखिम लेने से भी बचने लगे हैं। सिंघल ने कहा कि पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन (थ्दम्ब्ब्दैह) के बाद जिस तरह डिमांड बढ़ी थी, अब उसका असर भी कम होने लगा है। शहरी इलाकों के साथ अब ग्रामीण इलाकों के लोगों के खर्च पर भी लगाम लगने लगा है, क्योंकि कोरोनावायरस गांव में भी फैलने लगा है।

पिछले वित्त वर्ष के जीडीपी नंबर्स

भारत में मई में ही पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आने हैं। जीडीपी के इन आंकड़ों पर कोरोनावायरस की मौजूदा स्थिति का असर नहीं देखा जाएगा। कोरोनावायरस संकट के मौजूदा चरण में भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी दबाव बढ़ा है और कई राज्यों में संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है।

रिजर्व बैंक का अनुमान

सोमवार को ही भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन में कहा था कि कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण की वजह से मांग पर काफी असर पड़ा है। लोगों की आवाजाही बंद होने की वजह से उनका खर्च घटा है। इसके साथ ही रोजगार के अवसर कम होने की वजह से भी लोगों ने बचत करना शुरू किया है। कोरोना के मौजूदा संकट से निबटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति में ढील दी है और निचले स्तर से जीडीपी ग्रोथ में कुछ सुधार लाने के लिए तरलता बढ़ाने की कई पहल की है।

गूगल ने भारत में न्यूज शोकेस पेश किया 50 हजार पत्रकारों, छात्रों को प्रशिक्षित करेगी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

गूगल ने मंगलवार को भारत में 30 समाचार संगठनों के साथ अपने न्यूज शोकेस की पेशकश की, जिसका मकसद गूगल के समाचार और खोज मंचों पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदर्शित करने के लिए प्रकाशकों को प्रोत्साहित करना और समर्थन देना है। इसके साथ ही गूगल भारत में अगले तीन वर्षों के दौरान समाचार संगठनों और पत्रकारिता विद्यालयों के 50,000 पत्रकारों और पत्रकारिता के छात्रों को डिजिटल हुनर सिखाएगा। गूगल के उपाध्यक्ष (उत्पाद प्रबंधन) ब्रैड बेंडर ने कहा, "हम अब प्रकाशकों की मदद के लिए न्यूज शोकेस पेश कर रहे हैं, ताकि लोगों को भरोसेमंद खबर मिल सके, विशेष रूप से इस महत्वपूर्ण समय में जब कोविड संकट जारी है। समाचार शोकेस दल प्रकाशकों की पसंद के अनुसार लेखों को बढ़ावा देता है, और उन्हें खबर के साथ अतिरिक्त संदर्भ देने की अनुमति भी देता है, ताकी पाठकों में इस बात की बेहतर समझ बन सके कि उनके आसपास क्या हो रहा है।"उन्होंने कहा कि ये समाचार दल ब्रांडिंग सुनिश्चित करते हैं, और उपयोगकर्ताओं को प्रकाशकों की वेबसाइट पर ले जाते हैं। गूगल न्यूज शोकेस भारत में 30 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय समाचार संगठनों के साथ शुरू किया गया है और आने वाले दिनों में इस संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। गूगल की यह सेवा जर्मनी, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, चेकिया, इटली और अर्जेंटीना सहित एक दर्जन से अधिक देशों में उपलब्ध है। भारत में गूगल के कंट्री हेड और उपाध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में समाचारों की खपत बढ़ रही है, वहीं उपभोक्ता आदतों में बदलाव भी आ रहा है, जिसमें अधिक युवा उपभोक्ता समाचार के लिए डिजिटल पहुंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि कंपनी अगले तीन वर्षों में 50,000 से अधिक पत्रकारों और पत्रकारिता के छात्रों को प्रशिक्षित करेगी और इसके तहत खबरों के सत्यापन, फेक न्यूज से निपटने के उपायों और डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल पर खासतौर से ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अप्रैल में 57.25 लाख लोगों ने घरेलू विमान यात्राएं की, आंकड़ा मार्च से 26.8 प्रतिशत कमः डीजीसीए

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय विमानन नियामक डीजीसीए ने मंगलवार को कहा कि अप्रैल महीने में 57.25 लाख लोगों ने घरेलू विमान यात्राएं कीं जो मार्च की तुलना में 26.8 प्रतिशत कम है। मार्च का आंकड़ा 78.22 लाख था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुसार फरवरी में देश के अंदर 78.27 लाख लोगों ने विमान यात्रा की थी। अप्रैल में वायु यातायात में आयी कमी की वजह कोविड-19 की दूसरी लहर है जिसने भारत और उसके विमानन क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। डीजीसीए के आंकड़े के अनुसार अप्रैल में इंडिगो ने सबसे ज्यादा 30.83 लाख यात्री पहुंचाए जो कुल घरेलू बाजार का 53.9 प्रतिशत हिस्सा है। इसके बाद स्पाइसजेट ने 7.05 लाख (12.3 प्रतिशत), एयर इंडिया ने 6.85 लाख, गो एयर ने 5.47 लाख, एयर एशिया इंडिया ने 3.55 लाख और विस्तार ने 3.11 लाख यात्रियों को अपनी सेवाएं दीं। आंकड़े के अनुसार अप्रैल में शीर्ष छह भारतीय एयरलाइनों की उड़ानों में क्षमता के 52 से 70.08 प्रतिशत के बीच यात्री ही ही सवार थे।

रिजर्व बैंक ने मार्च में शुद्ध रूप से 5.699 अरब डालर बेचे

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

रिजर्व बैंक ने मार्च में अमेरिका मुद्रा की शुद्ध रूप से बिकवाली की। केन्द्रीय बैंक ने मार्च के दौरान हाजिर बाजार में शुद्ध रूप से 5.699 अरब डालर की अमेरिकी मुद्रा की बिक्री की। आरबीआई के आंकड़ों में यह दर्शाया गया है। आरबीआई के मई 2021 के मासिक बुलेटिन के मुताबिक केन्द्रीय बैंक ने मार्च 2021 में हाजिर मुद्रा बाजार से 20.25 अरब डालर की खरीदारी की वहीं इस दौरान उसने 25.949 अरब डालर बाजार में बेचे। इस प्रकार शुद्ध रूप से उसने 5.699 अरब डालर बाजार में बेचे। इससे पिछले महीने फरवरी 2021 में भी शीर्ष बैंक ने शुद्ध रूप से डालर की बिक्री की। फरवरी में आरबीआई ने 23.352 अरब डालर की खरीदारी और 24.571 अरब डालर की हाजिर बाजार में बिक्री की। वित्त वर्ष 2019- 20 की यदि बात की जाये तो वर्ष के दौरान आरबीआई ने शुद्ध रूप से 45.097 अरब डालर की खरीद की। इस दौरान बैंक ने 72.205 अरब डालर खरीदे वहीं 27.108 अरब डालर बाजार में बेचे।

भारत में शुरू हुआ वैक्सीन टूरिज्म का क्रेज, जानिए मॉस्को के लिए क्या है पैकेज और कितनी चुकानी होगी कीमत

इस वक्त भारत में ओवरसीज टूरिज्म का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अभी मॉस्को लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। दिल्ली की एक ट्रैवल एजेंसी ने तो 24 दिन का टूर पैकेज भी ऑफर करना शुरू कर दिया है, जिसकी कीमत करीब 1.30 लाख रुपये (price of vaccine tourism package to moscow) है। इस टूर पैकेज (Vaccine tourism package offer) के तहत रूस जाकर स्पूतनिक-वी वैक्सीन (corona vaccine Sputnik-v) लगवाने के इच्छुक लोग बुकिंग करा सकते हैं। स्पूतनिक की 2 डोज के बीच 21 दिन का समय है और इतने दिनों में लोगों को वहां की तमाम लोकप्रिय जगहें घुमाई जाएंगी।

खुद स्पूतनिक-वी ने किया था वैक्सीज टूरिज्म पर ट्वीट

ट्रैवल एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मॉस्को पहुंचने के अगले दिन लगेगी। विदेशी लोग रूस में अगर कम से कम 7 दिन रहते हैं तो वह वैक्सीन लगवा सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ पहले से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत होती है, जो ये ट्रैवल एजेंसी कर रही है। स्पूतनिक-वी ने 1 अप्रैल को अपने ट्विटर अकाउंट पर वैक्सीन टूरिज्म पर एक टीजर भी ट्वीट किया था। इसके साथ ही लिखा गया था कि जैसे ही उनका ये प्रोग्राम शुरू होता है, लोग रूस आकर स्पूतनिक-वी वैक्सीन लगवा सकते है। उसके बाद से अब तक इस पर कोई अपडेट नहीं था।

पहला बैच हो चुका है रवाना, दूसरा भी है जाने वाला

दिल्ली की ट्रैवल एजेंसी के अनुसार वैक्सीन टूरिज्म के पैकेज के तहत पहला बैच 15 मई को मॉस्को के लिए रवाना हो चुका है, जिसमें कुल 30 लोग हैं। इसमें अधिकतर लोग गुरुग्राम के डॉक्टर हैं, जिन्हें पहली डोज लग चुकी है। दूसरा बैच 29 मई को रवाना होगा, जिसकी बुकिंग फुल हो चुकी है, जिसमें अधिकतर दिल्ली के डॉक्टर हैं। इसके बाद जून के महीने में कुछ बैच मॉस्को के लिए रवाना होंगे।

कौन-कौन से खर्च शामिल हैं इस पैकेज में?

ट्रैवल अजेंसी के अनुसार लोगों का ग्रुप 3 दिन सेंट पीट्सबर्ग में बिताता है और बाकी के दिन मॉस्को में। इस पैकेज में हवाई यात्रा का टिकट, ब्रेकफास्ट, डिनर और कुछ दिनों वहां घूमने का खर्च शामिल है। हालांकि, 10 हजार रुपये की वीजा फीस इस पैकेज का हिस्सा नहीं है। अभी रूस उन कुछ देशों में से एक है, जो भारतीयों को वैक्सीन वैकेशन की इजाजत दे रहा है। हालांकि, इसके लिए आपको नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट लेकर जाना होगा और आपके पहुंचने पर आपके क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।